



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042024-253482  
CG-DL-E-01042024-253482

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 30, 2024/चैत्र 10, 1946

No. 92]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 30, 2024/CHAITRA 10, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2024

मामला सं.- सीवीडी (ओआई)-01/2024

विषय: चीन जन. गण. में उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यात किए जाने वाले ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए प्रभाव पिंगमेंट को छोड़कर, इफेक्ट पियरलेसेंट पिंगमेंट या अभ्रक पियरलेसेंट पिंगमेंट के आयात से संबंधित प्रतिकारी शुल्क जांच की शुरुआत।

फा. सं. 6/08/2024-डीजीटीआर.—1. सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (इसके बाद सुदर्शन या आवेदक या घरेलू उद्योग के रूप में संदर्भित) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के तहत नामित प्राधिकारी (इसके बाद 'प्राधिकरण' के रूप में संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (पहचान, सब्सिडी वाली वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क का आकलन और संग्रह और क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है (इसके बाद "सीवीडी नियम" या "नियम" के रूप में भी संदर्भित किया गया है) ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए प्रभाव वर्णक को छोड़कर, 'प्रभाव पर्लेसेंट पिंगमेंट या अभ्रक पर्लेसेंट पिंगमेंट' के आयात से संबंधित एक प्रतिकारी झूठी जांच शुरू करने के लिए (इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" या "विषय माल" के रूप में संदर्भित किया गया है या "पीयूसी") चीन जन. गण. से उत्पन्न या निर्यात किया जाता है (इसके बाद "विषय देश" के रूप में संदर्भित)।

**क. सब्सिडी का आरोप**

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबंधित देश में विषय वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों को संबंधित देश की सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रदान की जाने वाली कार्रवाई योग्य सब्सिडी से लाभ हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रांतों और नगर पालिकाओं की सरकारें शामिल हैं जिनमें उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं, और अन्य 'सार्वजनिक निकाय' शामिल हैं। आवेदक ने संबंधित कानूनों, नियमों और विनियमों और संबंधित सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक निकायों की अन्य अधिसूचनाओं पर भरोसा किया है जैसा कि सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और अन्य जांच प्राधिकरणों के निर्धारण में जिन्होंने ऐसी योजनाओं की व्यापक जांच की थी और प्रतितुलनीय सब्सिडी कार्यक्रमों के अस्तित्व का निष्कर्ष निकाला था।

**ख. परामर्श**

3. सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों (एएससीएम) पर समझौते के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में, चीन जन. गण. की सरकार को पूर्व-दीक्षा परामर्श के लिए आमंत्रित किया गया था। तथापि, इसने उपर्युक्त अवसर का लाभ नहीं उठाया।

**ग. सब्सिडी कार्यक्रम**

4. आवेदक द्वारा प्रदान किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य से पता चलता है कि संबंधित देश में विषय वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों को कई सब्सिडी योजनाओं/कार्यक्रमों से लाभ हुआ है, जो विषय देश की सरकार और/या इसके सार्वजनिक निकायों द्वारा नीचे सूचीबद्ध हैं। कथित सब्सिडी में धन का प्रत्यक्ष हस्तांतरण और धन या देनदारियों का संभावित प्रत्यक्ष हस्तांतरण शामिल है; सरकारी राजस्व जो अन्यथा देय है, वह पूर्ववत है या एकत्र नहीं किया गया है; पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान; अधिमानी वित्तपोषण, उधार और निर्यात ऋण आदि।

**क. अनुदान के रूप में कार्यक्रम**

- 1) कार्यक्रम संख्या 1: अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) सहायता अनुदान।
- 2) कार्यक्रम संख्या 2: विदेशी आर्थिक और व्यापार विकास के लिए विशेष कोष।
- 3) कार्यक्रम संख्या 3: औद्योगिक परिवर्तन और उन्नयन के लिए निधि / तकनीकी उन्नयन, नवीकरण या परिवर्तन से संबंधित अनुदान।
- 4) कार्यक्रम संख्या 4: ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी सुधार / परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विशेष निधि / ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी के परिवर्तन के लिए प्रोत्साहन निधि / ऊर्जा बचत, संरक्षण और उत्सर्जन अनुदान।
- 5) कार्यक्रम संख्या 5: ग्रीन फैक्ट्री के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।
- 6) कार्यक्रम संख्या 6: चीन के प्रसिद्ध ब्रांड।
- 7) कार्यक्रम संख्या 7: निर्यात सहायता अनुदान।
- 8) कार्यक्रम संख्या 8: स्थानीय सरकारों द्वारा पाटन रोधी और/या प्रतिकारी कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति (पाटन रोधी प्रतिवादी सहायता)।
- 9) कार्यक्रम संख्या 9: राज्य कुंजी प्रौद्योगिकी नवीकरण परियोजना कोष।
- 10) कार्यक्रम संख्या 10: विभिन्न सरकारी अनुदान- प्रांतीय और नगर पालिका/क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए चीन जन. गण. / तदर्थ अनुदान के उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- 11) कार्यक्रम संख्या 11: गुआंगशी प्रांत में बौद्धिक संपदा पुरस्कार।

**ख. कर और वैट प्रोत्साहन के रूप में कार्यक्रम**

- 12) कार्यक्रम संख्या 12: निर्यात पर निर्यात कर छूट /
- 13) कार्यक्रम संख्या 13: पश्चिमी क्षेत्रों में अधिमानी कर नीतियां।
- 14) कार्यक्रम संख्या 14: उच्च और नई प्रौद्योगिकी कंपनियों के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों के लिए अधिमानी कर नीतियां।
- 15) कार्यक्रम संख्या 15: अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) खर्चों की कटौती के लिए कर नीतियां।

- 16) कार्यक्रम संख्या 16: विशेष उपकरणों की खरीद से संबंधित टैक्स क्रेडिट।
- 17) कार्यक्रम संख्या 17: फूज़ौ युआनहोंग निवेश क्षेत्र कर में स्थापित उद्यमों के लिए कर राहत।
- 18) कार्यक्रम संख्या 18: अचल संपत्तियों का त्वरित मूल्यहास।

**ग. पर्याप्त पारिश्रमिक (एलटीएआर) से कम के लिए माल और सेवाओं के प्रावधान के रूप में कार्यक्रम**

- 19) कार्यक्रम संख्या 19: पर्याप्त पारिश्रमिक (एलटीएआर) से कम के लिए प्रदान किए गए भूमि / भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान।
- 20) कार्यक्रम संख्या 20: पर्याप्त पारिश्रमिक (एलटीएआर) से कम पर बिजली का प्रावधान।
- 21) कार्यक्रम संख्या 21: आर्थिक विकास क्षेत्रों में एलटीएआर के लिए भूमि उपयोग अधिकार।
- 22) कार्यक्रम संख्या 22: एलटीएआर के लिए राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों (एसओई) को भूमि का प्रावधान।
- 23) कार्यक्रम संख्या 23: एलटीएआर के लिए कास्टिक सोडा का प्रावधान।
- 24) कार्यक्रम संख्या 24: एलटीएआर के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का प्रावधान।
- 25) कार्यक्रम संख्या 25: एलटीएआर के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रावधान।

**घ. अधिमान्य वित्तपोषण, उधार और निर्यात ऋण के रूप में कार्यक्रम**

- 26) कार्यक्रम संख्या 26: जावक निवेश करने वाली कंपनियों के लिए वन बेल्ट वन रोड पहल के तहत अधिमान्य वित्तपोषण।
- 27) कार्यक्रम संख्या 27: प्रभाव पिगमेंट उद्योग के लिए अधिमान्य ऋण और ब्याज दरें।
- 28) कार्यक्रम संख्या 28: निर्यात ऋण बीमा सब्सिडी।
- 29) कार्यक्रम संख्या 29: जीओसी द्वारा ऋण गारंटी /
- 30) कार्यक्रम संख्या 30: इक्विटी स्वेप के लिए ऋण।
- 31) कार्यक्रम संख्या 31: निर्यात विक्रेता का क्रेडिट।
- 32) कार्यक्रम संख्या 32: निर्यात क्रेता का क्रेडिट।

5. यह आरोप लगाया गया है कि उपर्युक्त योजनाएं सब्सिडी हैं क्योंकि इनमें विषय देश की सरकार या सार्वजनिक निकाय से वित्तीय योगदान शामिल है, जो प्राप्तकर्ताओं को लाभ प्रदान करता है। इन योजनाओं को कुछ उद्यमों या उद्यमों के समूहों और/या उत्पादों और/या क्षेत्रों तक सीमित करने का भी आरोप लगाया जाता है और इसलिए विशिष्ट और प्रतिकारी हैं।
6. नामित प्राधिकारी अन्य सब्सिडियों की जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो जांच के दौरान संबंधित देश में विषय वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा मौजूद और प्राप्त की जा सकती हैं।

**घ. क्षति और कारण लिंक का आरोप**

7. आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर चीन से राजसहायता प्राप्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि भारतीय मांग, उत्पादन और कुल आयात के संबंध में आयात अधिक है, भले ही आवेदक के पास भारत में पूरी मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता हो। विषय आयात आवेदक की कीमतों और लागत को कम कर रहे हैं। क्षति की अवधि में आवेदक की बिक्री की लागत में वृद्धि हुई है। बिक्री मूल्य में गिरावट आई है जो बिक्री लागत से कम रही है जो कीमतों को निराशाजनक और आयातों के प्रभाव को दर्शाती है। जबकि आवेदक के उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है, आवेदक को आयात के कारण मूल्य क्षति हुई है। आवेदक की लाभप्रदता बिगड़ गई है, और इसने हाल की अवधि में नियोजित पूंजी पर वित्तीय नुकसान, नकद नुकसान और नकारात्मक रिटर्न दिया है। आवेदक के इन्वेंट्री स्तर में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य प्रथम दृष्टया चीन से कथित राजसहायता प्राप्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति दर्शाते हैं।

**ड. जांच की शुरुआत**

8. आवेदक द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और सब्सिडी और आवेदक को परिणामी क्षति की पुष्टि करने वाले आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर खुद को संतुष्ट करने के बाद, प्राधिकरण कथित तौर पर सब्सिडी विरोधी जांच शुरू करता है। नियमों के नियम 6 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 9 के अनुसार आवेदक को सब्सिडी और परिणामी भौतिक क्षति, कथित सब्सिडी के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और प्रतिकारी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए, जो कि लगाया जाएगा। घरेलू उद्योग को लगी क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त है।

**च. घरेलू उद्योग और स्थिति**

9. नियम 2 (बी) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

"घरेलू उद्योग" से घरेलू उत्पादक अभिप्रेत है जो संपूर्ण वस्तु या घरेलू उत्पादक हैं, जिनका सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है, सिवाय इसके कि जब ऐसे उत्पादक कथित सब्सिडी वाली वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों, या स्वयं उसके आयातक हों, जिस मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

10. आवेदन सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि सुदर्शन भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने यह भी बताया है कि उन्होंने संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वे संबंधित देश में संबंधित वस्तुओं के किसी निर्यातक या भारत में संबंधित वस्तुओं के आयातक से संबंधित नहीं हैं। तदनुसार, प्राधिकरण प्रथम दृष्टया मानता है कि आवेदक सीवीडी नियमों के नियम 2 (बी) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग का गठन करता है, और आवेदन नियम 6 (3) के तहत खड़े होने की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

**छ. विचाराधीन उत्पाद**

11. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "प्रभाव पर्लेसेंट पिगमेंट या अभ्रक मोती वर्णक है, ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए प्रभाव वर्णक या अभ्रक मोती वर्णक को छोड़कर।
12. ये अकार्बनिक रंगद्रव्य/रंग एजेंट हैं जो चमकदार/चमकदार/पाले सेओढ़ लिया प्रभाव देते हैं। इन्हें व्यावसायिक रूप से 'पर्ले लस्टर पिगमेंट' या 'पर्ले पिगमेंट' के रूप में भी जाना जाता है। वे सूखे पाउडर के रूप में बेचे जाते हैं और बड़े पैमाने पर कोटिंग, स्याही और प्लास्टिक के आवेदन के लिए रंग और अन्य प्रभाव प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन मोती पिगमेंट में अलग-अलग गुण (झिलमिलाना, चमक और चमक) होते हैं जो अंतिम अनुप्रयोगों में अद्वितीय प्रभाव प्रदान करते हैं। वर्णक के इन विशिष्ट ऑप्टिकल प्रभावों को मोती प्रभाव के रूप में जाना जाता है।
13. इन पिगमेंट को प्राकृतिक या सिंथेटिक अभ्रक से निर्मित किया जा सकता है। कोई भी निर्माता विभिन्न कण आकारों के साथ पिगमेंट की आपूर्ति कर सकता है और अंतिम उपभोक्ता की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप पिगमेंट तैयार कर सकता है। लागत और कीमतें वर्णक के औसत आकार और रंग के साथ भिन्न होती हैं।
14. अभ्रक मोती वर्णक सोने, चांदी, इंद्रधनुषी, कांस्य, तांबा, मैरून जैसे मिट्टी के रंगों और अलग-अलग कण आकार सहित विभिन्न रंगों के हो सकते हैं।
15. अभ्रक मोती पिगमेंट को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 32 के तहत शीर्षक 3206 के तहत वर्गीकृत किया गया है। 4-अंकीय स्तर पर इन पिगमेंट को सौंपे गए कोड के अलावा, विषय वस्तुओं को विभिन्न एचएसएन कोड के तहत भी आयात किया जा रहा है: 32041720, 32041739, 32041759, 32041790, 32071040, 32129090 और 32151990। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। प्राधिकरण विचाराधीन उत्पाद के आयात पर विचार करेगा, चाहे वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए इसका वर्गीकरण कुछ भी हो।
16. घरेलू उद्योग ने निष्पक्ष तुलना के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है:

वर्णक का प्रकार	N - प्राकृतिक अभ्रक वर्णक S - सिंथेटिक वर्णक
अनुप्रयोग	1 - औद्योगिक गैर-मोटर वाहन 2 - कॉस्मेटिक
रंग	S - सिल्वर G - सोना I - इंद्रधनुषी E - पृथ्वी टोन (कांस्य/तांबा/मैरून) O - अन्य
कण आकार (D50)	1 - सुपर फाइन (15 से नीचे) 2 - ठीक (15-20) 3 - मध्यम (20.1-30) 4 - बड़ा (30.1-50) 5 - बहुत बड़ा (50 से ऊपर)

17. वर्तमान जांच के पक्षकार प्राधिकरण के समक्ष दायर आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 15 दिनों के भीतर पीयूसी और प्रस्तावित पीसीएन, यदि कोई हो, पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं, जैसा कि इस जांच शुरुआत अधिसूचना के पैराग्राफ 26 में दर्शाया गया है।

#### ज. समान वस्तु

18. आवेदक ने कहा है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और विषय देश से निर्यात की गई वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित और चीन से आयातित लेख भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन, और विषय वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। आवेदक द्वारा निर्मित विषय वस्तुएं और लेख तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। आवेदक ने दावा किया है कि पीयूसी के उपभोक्ता संबंधित वस्तुओं और आवेदक द्वारा निर्मित वस्तु का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच शुरू करने के प्रयोजनों के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित विषय वस्तुओं को चीन से आयात किए जा रहे उत्पाद के लेख की तरह माना जा रहा है।

#### झ. शामिल देश

19. आवेदन चीन जन गण में उत्पन्न या उससे निर्यातित विषय वस्तुओं के कथित सब्सिडी के संबंध में दायर किया गया है। इसलिए, वर्तमान जांच के लिए विषय देश चीन जन. गण. है।

#### ञ. जांच की अवधि

20. प्राधिकरण ने अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 (12 महीने) के बीच की अवधि को जांच की अवधि (इसके बाद "पीओआई" के रूप में संदर्भित) और वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 को वर्तमान जांच के उद्देश्य से क्षति की अवधि के रूप में माना है।

#### ट. सूचना प्रस्तुत करना

21. सभी संचार ईमेल पते पर ईमेल के माध्यम से प्राधिकरण को भेजे जाने चाहिए [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in) ; [adg14-dgtr@gov.in](mailto:adg14-dgtr@gov.in) ; [dir11-dgtr@gov.in](mailto:dir11-dgtr@gov.in) ; [dd16-dgtr@gov.in](mailto:dd16-dgtr@gov.in)। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सबमिशन का कथा भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में है और डेटा फाइलें एमएस एक्सेल प्रारूप में हैं।
22. संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, उनकी सरकार को भारत में उनके दूतावास के माध्यम से और भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं को संबंधित वस्तुओं से संबंधित होने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें।
23. कोई अन्य इच्छुक पार्टी भी ऊपर उल्लिखित ईमेल पतों पर नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से जांच के लिए अपनी प्रस्तुतियाँ प्रासंगिक बना सकती है।
24. प्राधिकरण के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पार्टियों को उसी का गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

25. इच्छुक पार्टियों को आगे सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.dgtr.gov.in/> पर नियमित नजर रखें।

#### ठ. अंतिम तिथि

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी ईमेल पते पर ईमेल के माध्यम से प्राधिकरण को भेजी जानी चाहिए [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in) ; [adg14-dgtr@gov.in](mailto:adg14-dgtr@gov.in) ; [dir11-dgtr@gov.in](mailto:dir11-dgtr@gov.in) ; [dd16-dgtr@gov.in](mailto:dd16-dgtr@gov.in) उस तारीख से तीस दिनों (30 दिनों) के भीतर जब घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का गैर-गोपनीय संस्करण नामित प्राधिकारी द्वारा परिचालित किया जाएगा या सीवीडी नियमों के नियम 7 (4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय-सीमा में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकरण अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमों के अनुसार अपने निष्कर्षों को अभिलिखित कर सकेगा।
27. जो पक्ष विषय जांच में भाग लेना चाहते हैं, वे इस जाँच शुरुआत अधिसूचना के पैराग्राफ 26 में दर्शाई गई समय-सीमा के भीतर नामित प्राधिकारी के साथ खुद को पंजीकृत कर सकते हैं , जो स्पष्ट रूप से उनकी रुचि की प्रकृति को दर्शाता है। इच्छुक पार्टी के रूप में पंजीकरण के लिए बाद के चरण में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
28. जहां एक इच्छुक पार्टी प्रस्तुतियाँ दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय चाहती है, उसे सीवीडी नियम, 1995 के नियम 7 (4) के संदर्भ में इस तरह के विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और इस तरह के अनुरोध को इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

#### ड. गोपनीय आधार पर जानकारी प्रस्तुत करना

29. जहां वर्तमान जांच का कोई पक्षकार प्राधिकरण के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतियाँ करता है या गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, वहां ऐसे पक्ष को सीवीडी नियमों के नियम 8 के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार नोटिसों के अनुसार ऐसी जानकारी का एक गैर-गोपनीय संस्करण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
30. सबमिशन को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। ऐसे चिह्नों के बिना प्राधिकरण को किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण को प्राधिकरण द्वारा गैर-गोपनीय जानकारी के रूप में माना जाएगा, और प्राधिकरण अन्य इच्छुक पक्षों को ऐसे सबमिशन का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।
31. गोपनीय संस्करण में वे सभी जानकारी शामिल होंगी, जो स्वभावतः, गोपनीय और/या अन्य जानकारी है, जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना के लिए जिसे प्रकृति द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है, या वह सूचना जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।
32. इच्छुक पार्टियों द्वारा दायर की गई जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण गोपनीय जानकारी के साथ गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, अधिमानतः अनुक्रमित या खाली (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और ऐसी जानकारी को उचित और पर्याप्त रूप से सारांशित किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।
33. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के पदार्थ की उचित समझ की अनुमति देने के लिए गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाली पार्टी यह संकेत दे सकती है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और नियमों के नियम 8 के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण वाले कारणों का एक विवरण, 1995, और प्राधिकरण द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस, कि ऐसा संक्षेपण क्यों संभव नहीं है, प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।
34. इच्छुक पार्टियाँ किसी भी इच्छुक पार्टी द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकती हैं 7 प्राधिकरण के समक्ष दायर दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के संचलन की तारीख से दिन जैसा कि इस जाँच शुरुआत अधिसूचना के पैराग्राफ 26 में दर्शाया गया है।

35. गोपनीयता के दावे पर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी भी सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण या नियमों के नियम 8 के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त कारण कथन के बिना किया गया कोई भी प्रस्तुतिकरण, और प्राधिकरण द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस को प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
36. प्राधिकरण प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध वारंट नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।
37. प्राधिकरण संतुष्ट होने और प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी भी पार्टी को इसका खुलासा नहीं करेगा।
38. पंजीकृत इच्छुक पार्टियों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, साथ ही उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने सबमिशन के गैर-गोपनीय संस्करण और अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को ईमेल करें। सबमिशन के गैर-गोपनीय संस्करण को प्रसारित करने में विफलता से इस जाँच शुरुआत अधिसूचना की धारा 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है।

#### द. असहयोग

39. यदि कोई इच्छुक पक्ष उचित अवधि के भीतर या इस जाँच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के भीतर या बाद में अलग संचार के माध्यम से प्रदान की गई समय अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकरण ऐसे इच्छुक पक्ष को असहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है फिट समझे।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

#### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2024

Case No. CVD (OI) - 01/2024

**Subject: Initiation of countervailing duty investigation concerning imports of effect pearlescent pigments or mica pearlescent pigments, excluding effect pigments for automotive applications originating in or exported from China PR**

**F. No. 6/08/2024-DGTR.—1.** Sudarshan Chemical Industries Limited (hereinafter referred to as 'Sudarshan' or the 'applicant' or the 'domestic industry') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority') under the provisions of the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "CVD Rules" or the "Rules") for the initiation of a countervailing duty investigation concerning imports of 'effect pearlescent pigments or mica pearlescent pigments, excluding effect pigments for automotive applications' (hereinafter referred to as the "product under consideration" or the "subject goods" or the "PUC") originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the "subject country").

#### A. Allegation of subsidisation

2. The applicant has alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject country have benefitted from actionable subsidies provided at various levels by the government of the subject country, including the governments of different provinces and municipalities in which producers/exporters are located, and other 'public bodies'. The applicant has relied upon the relevant laws, rules and regulations, and other notifications of the relevant government agencies and public bodies as available in the public domain and in the determination of other investigating authorities who had conducted comprehensive investigations of such schemes and concluded the existence of countervailable subsidy programmes.

**B. Consultation**

3. In terms of Article 13 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM), the government of China PR was invited for pre-initiation consultations. However, it did not avail the above said opportunity.

**C. Subsidy Programs**

4. The *prima facie* evidence provided by the applicant shows that the producers and exporters of the subject goods in the subject country have benefitted from a number of subsidy schemes/programs, granted by the government of subject country and/or its public bodies as listed below. The alleged subsidies consist of direct transfer of funds and potential direct transfer of funds or liabilities; government revenue that is otherwise due is foregone or not collected; provision of goods and services for less than adequate remuneration; preferential financing, lending and export credit etc.

**a. Programs in the Form of Grants**

- 1) Program no.1: Research & Development (R&D) Assistance Grant.
- 2) Program no. 2: Special fund for foreign economic and trade development.
- 3) Program no. 3: Fund for Industrial Transformation and Upgrading / Grants related to technological upgrading, renovation or transformation.
- 4) Program no. 4: Special funds for energy saving technology reform / promotion of circular economy/ incentive fund for transformation of energy-saving technology/ Energy saving, conservation and emission grants.
- 5) Program no. 5: National Award for Green Factory.
- 6) Program no. 6: Famous Brands of China.
- 7) Program no. 7: Export Assistance Grant.
- 8) Program no. 8: Reimbursement of Anti-dumping and/or Countervailing Legal Expenses by the Local Governments (Anti-Dumping Respondent Assistance).
- 9) Program no. 9: The State Key Technology Renovation Project Fund.
- 10) Program no. 10: Various Government grants- Received by producers/exporters of China PR/ Ad hoc grants provided by provincial and municipal/regional authorities.
- 11) Program no. 11: Intellectual Property Awards in Guangxi Province.

**b. Programs in the form of Tax and Vat Incentives**

- 12) Program no. 12: Export tax rebate/Tax Refund on Exports.
- 13) Program no. 13: Preferential tax policies in the western regions.
- 14) Program no. 14: Preferential Tax Policies for companies that are recognized as high and new technology companies.
- 15) Program no. 15: Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses.
- 16) Program no. 16: Tax credit concerning the purchase of special equipment.
- 17) Program no. 17: Tax relief for enterprises set up in Fuzhou Yuanhong Investment Zone tax.
- 18) Program no. 18: Accelerated depreciation of fixed assets.

**c. Programs in the form of provision of goods and services for less than adequate remuneration (LTAR)**

- 19) Program No. 19: Provision of Land /Land Use rights provided for less than adequate remuneration (LTAR).
- 20) Program no. 20: Provision of Electricity at less than adequate remuneration (LTAR).
- 21) Program no. 21: Land-Use Rights for LTAR in Economic Development Zones.
- 22) Program no. 22: Provision of Land to State Owned Enterprises (SOEs) for LTAR.
- 23) Program no. 23: Provision of Caustic Soda for LTAR.
- 24) Program no. 24: Provision of Calcium Carbonate for LTAR.
- 25) Program no. 25: Provision of Titanium Dioxide for LTAR.

**d. Programs in the form of preferential financing, lending and export credit**



- 26) Program no. 26: Preferential Financing under One Belt One Road Initiative for Companies making Outward Investments.
  - 27) Program no. 27: Preferential Loans and Interest Rates to the Effect Pigments Industry.
  - 28) Program no. 28: Export Credit Insurance Subsidy.
  - 29) Program no. 29: Loan Guarantee/Credit Loan Guarantee by GOC/Export Credit Guarantees.
  - 30) Program no. 30: Debt for Equity Swaps.
  - 31) Program no. 31: Export Seller's Credit.
  - 32) Program no. 32: Export Buyer's Credit.
5. It has been alleged that the above-mentioned schemes are subsidies since these involve a financial contribution from the government of the subject country or a public body, which confer benefits on the recipients. These schemes are also alleged to be limited to certain enterprises or groups of enterprises and/or products and/or regions and are therefore specific and countervailable.
  6. The Designated Authority reserves the right to investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers/ exporters of the subject goods in the subject country, during the course of the investigation.

**D. Allegation of Injury and Causal Link**

7. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry because of subsidised imports from China. The applicant has claimed that the subject imports in relation to Indian demand, production and total imports are high, even when the applicant has sufficient capacity to cater to the entire demand in India. The subject imports are undercutting the prices and cost of the applicant. The cost of sales of the applicant increased has over the injury period. There has been a decline in selling price which has been below the cost of sales showing price depressing and suppressing effects of imports. While the production and domestic sales of the applicant have increased, the applicant has suffered price injury due to imports. The profitability of the applicant has deteriorated, and it has incurred financial losses, cash losses and negative return on capital employed in the recent period. There has also been an increase in the inventory levels of the applicant. Thus, the evidence provided by the applicant *prima facie* shows injury to the domestic industry caused by the alleged subsidized imports from China.

**E. Initiation of Investigation**

8. On the basis of the duly substantiated application by the applicant, and having satisfied itself, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicant substantiating the subsidization and consequent injury to the applicant, the Authority hereby initiates an anti-subsidy investigation into the alleged subsidization and consequent material injury to the applicant in accordance with Section 9 of the Act read with Rule 6 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged subsidization and to recommend the amount of countervailing duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**F. Domestic Industry and Standing**

9. Rule 2(b) defines domestic industry as follows:

“‘domestic industry’ means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidised article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry”

10. The application has been filed by Sudarshan Chemical Industries Limited. The applicant has submitted that it is the sole producer of the product under consideration in India. The applicant has further stated that it has not imported the subject goods from the subject country and that it is not related to any exporter of the subject goods in the subject country or importer of the subject goods in India. Accordingly, the Authority *prima facie* holds that the applicant constitutes domestic industry as defined under Rule 2(b) of the CVD Rules, and the application meets the requirements of standing under Rule 6(3).

**G. Product under Consideration**

11. The product under consideration in the present investigation is “*effect pearlescent pigments or mica pearlescent pigments, excluding effect pigments or mica pearlescent pigments for automotive applications.*”
12. These are inorganic pigments/colouring agents giving lustrous/shinning/frosted effects. These are commercially also known as ‘pearl lustre pigments’ or ‘pearl pigments’. They are sold as dry powder and are

extensively used to impart colours and other effects for coating, inks and plastic application. These pearl pigments have distinct properties (shimmer, lustre and sparkle) that provides unique effects in the end applications. These distinct optical effects of the pigment are referred to as the pearlescent effect.

13. These pigments can be manufactured from natural or synthetic mica. Any producer can supply pigments with different particle sizes and may tailor pigments to suit the specific requirements of the end consumer. Costs and prices vary with the mean size and colour of the pigment.
14. Mica pearl pigments can be of different shades including gold, silver, iridescent, earthy colours like bronze, copper, maroon, and in varying particle size.
15. Mica pearl pigments are classified under Chapter 32 of the Customs Tariff Act, 1975 under the heading 3206. Apart from the codes assigned to these pigments at 4-digit level, the subject goods are also being imported under different HSN codes: 32041720, 32041739, 32041759, 32041790, 32071040, 32129090 and 32151990. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration. The Authority shall consider imports of the product under consideration, irrespective of its classification for the purpose of the present investigation.
16. The domestic industry has proposed the following product control numbers (PCN) for the product under consideration for a fair comparison:

<b>Type of Pigment</b>	N - Natural mica pigment S - Synthetic Pigment
<b>Application</b>	1 - Industrial non-Automotive 2 - Cosmetic
<b>Colour</b>	S - Silver G - Gold I - Iridescent E - Earth tones (Bronze/ Copper/ Maroon) O - others
<b>Particle Size (D50)</b>	1 - Super fine (below 15) 2 - Fine (15-20) 3 - Medium (20.1-30) 4 - Large (30.1-50) 5 - Very large (above 50)

17. The parties to the present investigation may provide their comments on the PUC and proposed PCNs, if any, within 15 days of circulation of the non-confidential version of the application filed before the Authority as indicated in paragraph 26 of this initiation notification.

#### **H. Like Article**

18. The applicant has stated that there are no significant differences in the article produced by the applicant and exported from the subject country. The article produced by the applicant and imported from China are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. The applicant has claimed that consumers of the PUC are using the subject goods and the article manufactured by the applicant interchangeably. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated as like article to the product being imported from China.

#### **I. Country involved**

19. The application has been filed in respect of alleged subsidization of the subject goods originating in or exported from China PR. Therefore, the subject country for the present investigation is China PR.

#### **J. Period of investigation**

20. The Authority has considered the period between October 2022 to September 2023 (12 months) as the period of investigation (hereinafter referred to as the "POI") and financial years 2020-21, 2021-22, 2022-23 as the injury period for the purpose of the present investigation.

#### **K. Submission of Information**

21. All communication should be sent to the Authority via email at the email address [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in) ; [adg14-dgtr@gov.in](mailto:adg14-dgtr@gov.in) ; [dir11-dgtr@gov.in](mailto:dir11-dgtr@gov.in) ; [dd16-dgtr@gov.in](mailto:dd16-dgtr@gov.in). It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.

22. The known producers/exporters from the subject country, their government through their embassy in India and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
23. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email addresses mentioned hereinabove.
24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
25. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

**L. Time Limit**

26. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in) ; [adg14-dgtr@gov.in](mailto:adg14-dgtr@gov.in) ; [dir11-dgtr@gov.in](mailto:dir11-dgtr@gov.in) ; [dd16-dgtr@gov.in](mailto:dd16-dgtr@gov.in) within thirty days (30 days) from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 7(4) of the CVD Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.
27. Parties who wish to participate in the subject investigation may register themselves with the Designated Authority within the timelines as indicated in paragraph 26 of this initiation notification clearly indicating the nature of their interest. Any request at a later stage for registration as an interested party will not be entertained.
28. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 7(4) of the CVD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

**M. Submission of information on confidential basis**

29. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 8 of the CVD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
30. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as non- confidential information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
31. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
32. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
33. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
34. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by any interested party within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents filed before the Authority as indicated in paragraph 26 of this initiation notification.
35. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 8 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

36. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
37. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.
38. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions and other information to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions might lead to action under Section N of this initiation notification.

**N. Non-cooperation**

39. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequent time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority